made did not reveal existence of such Racket in the Armed Forces, as alleged.

Production of Sukhoi-30 aircraft

1222. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Government propose to get production of Sukhoi-30 fighter aircraft organised in the country to save rapid flow of foreign exchange; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) and (b) Yes, Sir. The Contract for procurement of SU-30MK aircraft provides for outright purchase of 40 aircraft with associated equipment and armament, followed by transfer of technology and licence production of the aircraft in India by HAL for subsequent supplies.

हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाना

1223. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे प्रस्तावित सुरंग निर्माण की अद्यतन स्थिति क्या है तथा इस पर अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या इस निर्माण कार्य को समयबद्ध बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू): (क) हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे में कोई सुरंग निर्माणाधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गोपनीय मामलों का लीक होना

1224. **श्री अजीत जोगी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुप्तचर तथा रक्षा संबंधी गोपनीय मामलों के लीक होने की कितनी घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इन मामलों में कौन-कौन से देश लिप्त पाये गये; और

(ग) सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू): (क) से (ग) गत दो वर्षों के दौरान रक्षा से संबंधित सूचना लीक होने की दो घटनाएं मंत्रालय की जानकारी में आई हैं। इन मामलों के संबंध में तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। दोनों मामलों में पाकिस्तानी कार्मिकों/एजेंटों के शामिल होने का संदेह है। रक्षा तथा भारत के अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों से संबंधित सूचना प्रकट करने के प्रयासों से संबंधित सरकारी गुप्त सूचना अधिनियम, 1923 के अंतर्गत आने वाले मामलों के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों/सी बी आई से पंद्रह मामले भी गृह मंत्रालय को प्राप्त हुए थे। इनमें से कुछ मामलों में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के शामिल होने का संदेह है। छह मामलों में गृह मंत्रालय द्वारा अभियोजन आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा शेष नौ मामले अधिकांशतः संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण लंबित हैं।

वर्गीकृत सूचना की सुरक्षा के लिए निर्धारित अनुदेश हैं। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरीक्षा भी की जाती है। जब भी वर्गीकृत सूचना के लीक होने के मामले के बारे में सूचना मिलती है, उसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है।

मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

1225. **श्री अजीत जोगी:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कितने भूतपूर्व सैनिक हैं और उनके पुनर्वास के लिए अब तक क्या कदम उठाए गये हैं;

(ख) क्या सरकार को राज्य के भूतपूर्व सैनिकों से पेंशन आदि के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) 1. 31 दिसंबर, 1996 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में विभिन्न जिला सैनिक बोर्डों में

कुल 24,648 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत किए गए थे। केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय योजनाएं/कार्यक्रम, जो मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में लागू हैं, इस प्रकार हैं:—

(1) केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह "ग" के 10% पद और समूह "घ" के 20% पद आरक्षित किए हैं। अर्द्ध सैन्य बलों में सहायक कमांडेंटों के दस प्रतिशत पद भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

(2) केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक समूह "ग" पदों में 14.5% और समूह "घ" पदों में 24.5% आरक्षण प्रदान करते हैं।

(3) भूतपूर्व सैनिकों को लघु उद्योग, सेवा उद्योग, होटल, नर्सिंग होम, पर्यटन परियोजनाएं, कृषि पर आधारित उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग आदि स्थापित करने के लिए स्व-रोजगार योजनाओं (सेमफेक्स) के तहत ऋण/वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जा रही है।

(4) भूतपूर्व सैनिकों ने कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के तत्वावधान में कोयले के परिवहन के लिए परिवहन कंपनियां भी स्थापित की हैं। इस समय, ये कंपनियां बिहार, उड़ीसा, मंध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कोयला-खानों में कार्य कर रही हैं।

(5) सरकार ने मरणोपरांत वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवाओं/आश्रितों, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाओं, युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों और शांतिकाल के दौरान 50% या उससे अधिक निशक्त हुए कार्मिकों के लिए 7.5% तेल उत्पाद एजेंसियों अर्थात् एल पी जी, मिट्टी के तेल की एजेंसियां और पेट्रोल पम्प आरक्षित किए हैं।

(6) कैंटीन स्टोर विभाग की सामान-सूची की कम प्रौद्योगिकी वाली मदों की 15% मदें भूतपूर्व सैनिक उद्यमियों के लिए आरक्षित हैं। रक्षा मंत्रालय ने भी रक्षा क्रय कार्यक्रमों के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों द्वारा निर्मित कम प्रौद्योगिकी वाली 10% मदें आरक्षित की हैं।

(7) भूतपूर्व सैनिक, यू टी आई एजेंसियों तथा श्रेणी-5 बी के अधिशेष वाहनों के आबंटन के लिए भी पात्र हैं।

2. मध्य प्रदेश सरकार भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह "ग" पदों में 9% तथा समूह "घ" पदों में 14% आरक्षण प्रदान कर रही है।

(ख) और (ग) वर्ष 1996 के दौरान मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों से रक्षा मंत्रालय में 54 याचिकाएं/अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे तथा समुचित समाधान के लिए संबंधित विभागों को भेज दिए गए थे।

Decision to shelve the Missile Development Programme

1226. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRI JANARDHANA POOJARY:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to shelve the missile development plan for the present and to resume it if the security situation warrants it; if so, the details of the decision taken; and

(b) the basis on which Government reached conclusion that India is not facing any threat to its security?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Intrusion by Pakistan into Indian Waters

1227. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Pakistan is intruding into Indian waters in Arabian Sea; and

(b) if so, the details thereof and the steps being taken in this regard?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I.K. GUJRAL): (a) and (b) Government have seen reports regarding Pakistan's notification specifying 'baselines' to measure Pakistan's territorial waters, the contiguous zone, the EEZ and continental shelf in the Arabian Sea.

Government have conveyed to Pakistan that while they reserve the right to seek